Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

जनवरी 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) 3
- ज़मीन की खरीद पर रोक 4
- 'कैशलेस' स्वास्थ्य सुविधा 4
- बढ़ती शीतकालीन वनाग्नि 5
- वर्ष 2023 में IPC के तहत 86% अपराध सुलझे 5
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय 6
- पीआरटी कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने के लिये आईजी ड्रोन 6
- बाघिन को बचाने का प्रयास 7
- उत्तराखंड को AYUSH के लिये एक प्रमुख गंतव्य बनाने की कार्य योजना 8
- उत्तराखंड में बाघों की आबादी 9
- राम मंदिर थीम पर उत्तरायणी पर्व 10
- सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के प्रयास 10
- उत्तराखंड में बनेंगे 5 हवाई अड्डे 11
- PMI ने उत्तर प्रदेश को 50 ई-बसें सौंपीं 11
- मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की योजना 12
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने थर्मल पावर प्लांटों के लिये कोयला ब्लॉक का अनुरोध किया 13
- केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी 13
- रक्षा मंत्री ने सीमा परियोजनाओं का अनावरण किया 13
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण की शुरुआत की 14
- उत्तराखंड ने पवलगढ़ कंज़र्वेशन रिज़र्व का नाम बदला 15
- उत्तराखंड के हवाई अड्डे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय होंगे 15
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जारी किया कैलेंडर 16
- 'विकसित उत्तराखंड' : गणतंत्र दिवस परेड की झाँकी 17
- गन्ने की किस्म का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) 19
- उत्तराखंड का जादुंग गाँव, पुनर्वास के लिये तैयार 19
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में किया 'रोड शो' 21
- पवित्र भूमि को जोड़ने वाली हवाई सेवा 21

नोट :

दृष्टि The Vision

उत्तराखंड

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC)

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी।

- UCC लागू करने का बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।

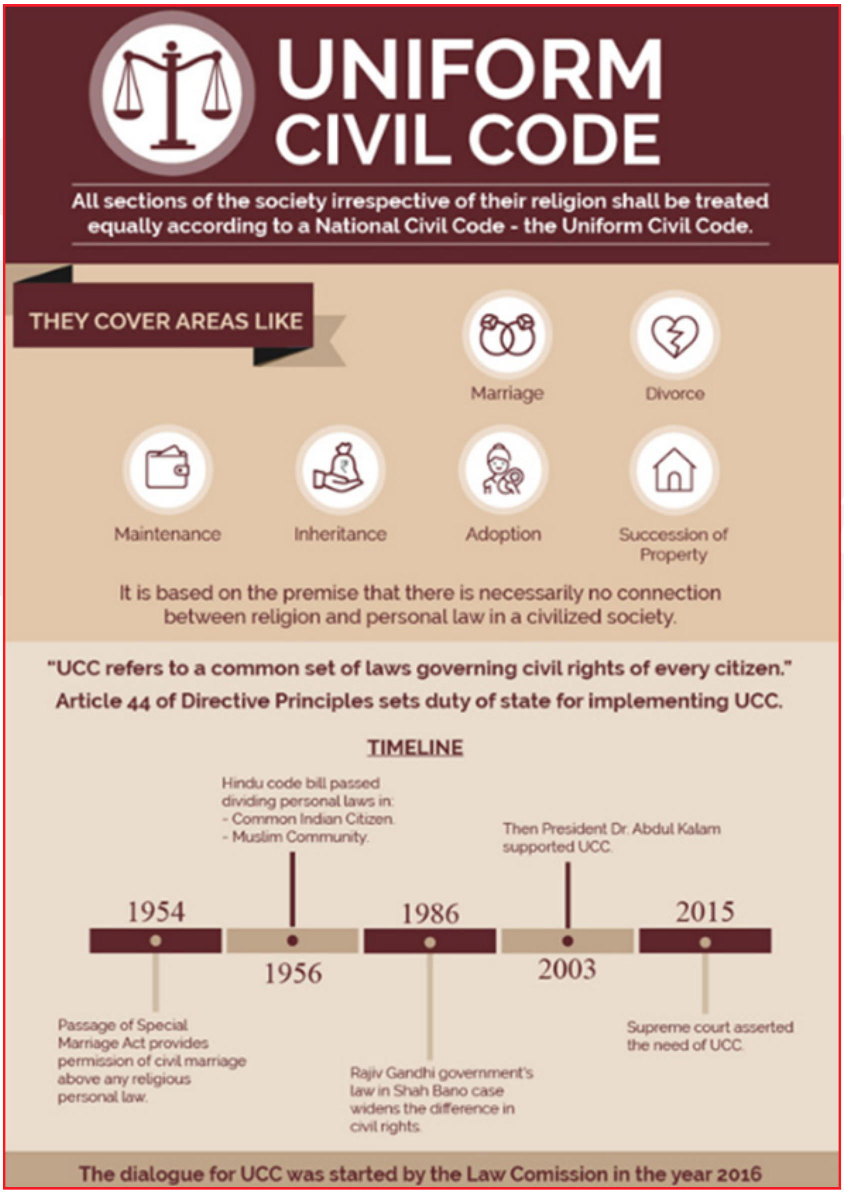

मुख्य बिंदु:

- UCC की परिकल्पना पूरे देश के लिये एक सामान कानून प्रदान करने की है, जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगा।
- संविधान के अनुच्छेद 44 अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) में से एक है।
  - अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" के उद्देश्य को मज़बूत करना है।
- गोवा एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है।

ज़मीन की खरीद पर रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिये बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु:

- आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) बाहरी लोगों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे।
- 22 दिसंबर, 2023 को सरकार ने भूमि कानूनों पर समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की विस्तृत जाँच के लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- सरकार कथित तौर पर जनता की भावनाओं के अनुरूप कदम उठा रही है, जिसे वह इस मामले में सर्वोपरि मानती है।
- सी. एम. धामी ने राज्य में औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिये भूमि की आवश्यकता और वर्तमान में उत्तराखंड में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु सिफारिशें करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था।
- जनता द्वारा विशिष्ट मांगें उठाई जा रही हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित सभी परियोजनाओं और उद्योगों में जहाँ भूमि अधिग्रहण या खरीद अनिवार्य है या भविष्य में की जाएगी, वहाँ 25% हिस्सेदारी स्थानीय ग्रामीणों हेतु और 25% हिस्सेदारी ज़िले के मूल निवासियों के लिये सुनिश्चित की जाए तथा इन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के लिये 80% रोज़गार सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- यह सुनिश्चित करने के लिये इन उपायों को लागू करना आवश्यक है कि राज्य के संसाधनों - जल (वाटर), जंगल (फारेस्ट), और ज़मीन (भूमि) पर पहला अधिकार मूल निवासियों का है ,ताकि स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार सुनिश्चित किया जा सके।

'कैशलेस' स्वास्थ्य सुविधा

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने नववर्ष के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों व उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का बड़ा तोहफा दिया है।

मुख्य बिंदु:

- राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का शुभारंभ किया।
- राज्य सरकार ने 1 नवंबर, 2023 को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने के लिये दो विभागों नामत: मत्सय व बागवानी के कर्मचारियों को शामिल करते हुए पायलट आधार पर योजना शुरू की थी।
  - सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने के लिये कवरेज का विस्तार किया गया है। इसके अलावा, इस योजना को बागवानी और मत्स्य पालन विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ IAS, IPS और IFoS के साथ-साथ उनके आश्रितों को शामिल करने के लिये पायलट आधार पर बढ़ाया जा रहा है।

- इसे सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों के लिये विस्तारित कर दिया गया है। इसके अलावा, इस योजना को पायलट आधार पर बागवानी और मत्स्य पालन विभाग, IAS, IPS एवं तथा IFoS के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों तक भी बढ़ाया जा रहा है।

- यह योजना आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।
- इसके अंतर्गत सूचीबद्ध प्रक्रियाएँ पूर्ण रूप से कैशलेस होंगी और अस्पताल को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एक ही प्लेटफॉर्म से उनके दावों को मंज़ूरी मिल जाएगी।
    - यह योजना लाभार्थियों एवं अन्य हितधारकों को अधिक कुशल, निर्बाध, परेशानी मुक्त और समयबद्ध सेवाएँ प्रदान करेगी।
- यह योजना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार न केवल छः जीवन-घातक आपात बिमारियों यानी हृदय संबंधी आपात स्थिति, मस्तिष्क रक्तस्राव, कोमा, बिजली का झटका, थर्ड व फोर्थ स्टेज कैंसर रोगी, और किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करती है, बल्कि यह लाभार्थियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी प्रकार के इनडोर उपचारों /डे केयर प्रक्रियाओं को भी कवर करती है।
- ये सेवाएँ इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) के पैनल में शामिल सभी अस्पतालों में लाभार्थियों के लिये उपलब्ध होंगी।
    - सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये सभी लाभार्थियों को ई-कार्ड/CCHF कार्ड जारी किया जाएगा।

बढ़ती शीतकालीन वनाग्नि

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड में शीत ऋतु में वनाग्नि में वृद्धि देखी जा रही है, यह घटना आमतौर पर 1 नवंबर से शुरू होती है।

मुख्य बिंदु:

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI), जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की सर्वोच्च संस्था है, ने 1 नवंबर, 2023 से 1 जनवरी, 2024 तक उत्तराखंड को 1006 अग्नि चेतावनी भेजी हैं। यह संख्या वर्ष 2022 में इसी अवधि के दौरान प्राप्त 556 अग्नि चेतावनियों की तुलना में काफी अधिक है।
    - उत्तरकाशी, नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ, पौडी और अल्मोडा ज़िलों में वनाग्नि की सूचना मिली है।
- वर्ष 2024 के पहले दिन नैनीताल में भीषण वनाग्नि की घटना देखी गई। ग्रामीणों ने इसका कारण पिछले तीन महीनों में वर्षा या बर्फबारी की अनुपस्थिति को बताया है, जिससे क्षेत्र शुष्क हो गया।
    - इस अग्नि से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि पशु अग्नि से बचने के लिये शहरी परिदृश्य की ओर विचरण करते हैं।
- वन कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित रूप से अपशिष्ट जलाना, किसानों द्वारा कृषि अवशेष जलाना, बंजर भूमि में ग्रामीणों द्वारा अपशिष्ट जलाना जैसे विभिन्न कारक वनाग्नि की घटनाओं का कारण बनते हैं।

वर्ष 2023 में IPC के तहत 86% अपराध सुलझे

चर्चा में क्यों?

राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के अनुसार, उत्तराखंड में वर्ष 2023 में भारतीय दंड संहिता के तहत कुल 15,797 अपराध के मामले दर्ज किये गए हैं, जो वर्ष 2022 की तुलना में 752 कम हैं, जिसमें 16,549 मामले दर्ज किये गए थे।

नोट:

भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के मद्देनज़र वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- वर्ष 2023 में सभी पंजीकृत अभियोगों में त्वरित कार्यवाही करते हुए 86% से अधिक मामलों का अनावरण कर 61% से अधिक अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

- वर्ष 2023 में कुल 432 वांछित अपराधी गिरफ्तार किये गए।
- राज्य पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत गिरफ्तार अभियुक्तों में से 30 अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति 186 करोड ज़ब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
- इसके अलावा वर्ष 2022 में गुण्डा एक्ट, 1982 के अन्तर्गत 262 अपराधियों के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही भी की गयी।
- वर्ष 2023 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में कुल 1,649 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 27 करोड़ रुपए की दवाएँ ज़ब्त की गईं।
- उत्तराखंड पुलिस की अग्निशमन इकाई ने कुल 1,381 दुर्घटनाओं को संबोधित किया, जिसमें 318 मानव जीवन और 121 करोड़ रूपए की संपत्ति बचाई गई।
- पुलिस ने विभिन्न उल्लंघनों के लिये वाहनों पर कुल 6.7 लाख चालानों में 37.06 करोड़ रूपए ज़ुर्माना वसूला गया।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय

चर्चा में क्यों?

1 जनवरी 2024 को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कौलागढ़, देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- इस भवन का शिलान्यास पिछले वर्ष मुख्यमंत्री धामी ने किया था, जिसे 4,09,40,000 रूपए की लागत से बनाया गया था।
  - आवासीय छात्रावास एवं छात्रावास में बच्चों को दी जा रही सुविधाओं के स्टॉक का निरीक्षण किया गया।
  - शिक्षा विभाग के अधिकारियों को छात्रावासों में बच्चों को बेहतर गुणवत्ता के संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए।
  - छात्रावास में 100 बच्चों के लिये आवासीय व्यवस्था की गई है।
- इस मौके पर सीएम ने घोषणा की कि कमज़ोर, वंचित और साधनहीन वर्ग की बेटियों की शिक्षा के लिये बनाए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास से सटे 11 स्कूलों में खोले गए छात्रावासों को इंटरमीडिएट स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा।
- कमज़ोर, पिछड़े, अनाथ और साधनहीन बच्चों की शिक्षा के लिये प्रदेश में 13 ऐसे छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 1,000 बच्चों के लिये नि:शुल्क व्यवस्था की गई है।
- बालिकाओं के लिये अलग से 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें सभी सुविधाएँ नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस:

- वह एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, जिनकी उद्दंड देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया।
- उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा डिवीज़न, बंगाल प्रांत में हुआ था।
  - उनकी जयंती को 'पराक्रम दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- उन्हें भारतीय सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना से एक अलग इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया गया, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में सहायता की।

पीआरटी कॉरिडोर का सर्वेक्षण करने के लिये आईजी ड्रोन

चर्चा में क्यों?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स कंपनी आईजी ड्रोन उत्तराखंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सर्वे करने जा रही है। यह नियो मेट्रो सिस्टम के तहत पर्सनलाइज़्ड रैपिड ट्रांज़िट कॉरिडोर (PRT) है।

- उत्तराखंड सरकार PRT कॉरिडोर परियोजना के वर्ष 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय तथा अत्याधुनिक आवागमन की सुविधा प्रदान करना है।

मुख्य बिंदु:

- नियो मेट्रो प्रोजेक्ट यातायात की भीड़ को कम करने के लिये अगले चार वर्षों में देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में अत्याधुनिक रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है।
- PRT को मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (MRTS) के तहत विकसित किया जा रहा है जो तीन शहरों- हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून को जोड़ेगा।
- आईजी ड्रोन हाई-टेक ड्रोन के माध्यम से परियोजना का सर्वेक्षण करके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने में मदद करेगा।
  - कंपनी भूमिगत कार्य प्रगति का नियमित अवलोकन करने के लिये घरेलू स्तर पर विकसित ड्रोन का उपयोग करेगी।
  - ड्रोन उन्नत सेंसर से लैस हैं जो ज़मीन से उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियाँ, वीडियो और अतिरिक्त डेटा कैप्चर करने में सक्षम हैं।
  - इस एकत्रित डेटा को आईजी वन, उनके स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जो तकनीकी रूप से गहन विश्लेषण प्रदान करता है।
  - ये विस्तृत आँकड़ें परियोजना की प्रगति की वास्तविक समय पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाते हैं।
- आईजी ड्रोन अग्रणी ड्रोन तकनीक और एनालिटिक्स कंपनी है जिसके द्वारा भारत का पहला 5जी ड्रोन- स्काईहॉक लॉन्च किया गया है।
- अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में ड्रोन का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, जो अपनी दक्षता, सटीकता और लागत-प्रभावशीलता के लिये मूल्यवान हैं।
  - इसके अनुप्रयोगों में निर्माण प्रगति का सर्वेक्षण, कार्य की गुणवत्ता का आकलन और निर्माण चरण के दौरान संभावित मुद्दों की पहचान करना आदि शामिल हैं।

बाघिन को बचाने का प्रयास

चर्चा में क्यों?

तराई पूर्वी वन प्रभाग की सुरई रेंज में पिछले एक साल से की निगरानी में रह रही बाघिन के पेट के पिछले हिस्से में फँसे तार को निकालने की कोशिश अंतिम पड़ाव पर पहुँच गयी है।

- हाल ही में तराई पूर्वी वन प्रभाग के सुरई रेंज में एक बाघिन, जिसके पेट के निचले हिस्से में एक साल से तार फँसा हुआ है, की बचाने के लिये दो पिंजरे लगाए गए हैं।
  - वन प्रभाग की सुरई रेंज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिज़र्व की महोफ रेंज के सेमल कुआँ वन क्षेत्र से सटी हुई है।

मुख्य बिंदु:

- जनवरी 2023 में जंगल में एक गश्ती दल ने बाघिन के पिछले पैरों से पहले पेट में तार का फंदा लिपटा हुआ देखा था।
- गश्ती दल द्वारा इस संबंध में उच्चाधिकारियों को सूचित करने के बाद मौके पर कैमरा ट्रैप लगाए गए और 35 में से 26 कैमरा ट्रैप ने बाघिन की नियमित तस्वीर खींची।
- बाघिन की निगरानी की रिपोर्ट उत्तराखंड वन्यजीव प्रतिपालक और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भेजी गयी जिस पर संयुक्त टीम का गठन हुआ तथा बाघिन को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की गयी।

पीलीभीत टाइगर रिज़र्व

- यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहाँपुर ज़िले में स्थित ऊपरी गंगा के मैदानी जैव-भौगोलिक प्रांत में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा है।
- रिज़र्व का उत्तरी किनारा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिह्नित है।

नोट :

- साल के जंगल, सघन घास के मैदान और नदियों से समय-समय पर बाढ़ द्वारा बनाए गए दलदल यहाँ की विशेषता है।
- रिज़र्व की सीमा पर शारदा सागर बाँध है जो 22 किमी. (14 मील) की लंबाई तक फैला है।
- इसे वर्ष 2014 में टाइगर रिज़र्व के रूप में नामित किया गया था।

उत्तराखंड को AYUSH के लिये एक प्रमुख गंतव्य बनाने की कार्य योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रदेश को आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (AYUSH) तथा वेलनेस के क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाने के लिये प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करने के निर्देश दिये।

मुख्य बिंदु:

- एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तराखंड में राज्य में जड़ी बूटियों के उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिये आयुष विभाग उद्यान तथा वन निगम से समन्वय कर संग्रह एवं विपणन की उचित व्यवस्था की जाएगी।
  - मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को विश्व का सर्वश्रेष्ठ योग गंतव्य बनाने हेतु नई योग नीति लाने के भी निर्देश दिये और पंचकर्म को बढ़ावा देने के लिये विशेष प्रयासों पर ज़ोर दिया।
  - आयुष के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये हर्बल उत्पादों के विपणन के लिये उचित मंच की व्यवस्था की जाएगी।
  - स्कूली विद्यार्थियों को आयुष से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिये सभी स्कूलों में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा आयुष नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के भी निर्देश दिये गए हैं।
  - आयुष में बेहतर कार्य हेतु वेलनेस केंद्र, आयुष सेवाओं के प्रामाणीकरण तथा चिकित्सकों एवं फार्मेशिस्टों को प्रसिद्ध आयुष विशेषज्ञों से प्रशिक्षण की व्यवस्था से आयुष चिकित्सा को जनता से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
- आयुष नीति में उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देना, अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनिवार्य पालन, नवीनतम ड्रोन-आधारित तकनीक का उपयोग, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और औषधीय पौधों के विक्रेताओं का विनियमन शामिल है।
- नीति में उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को प्रोत्साहन किये जाने, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज (GAP) के अंतर्राष्ट्रीय मानक का पालन किये जाने की अनिवार्यता, ड्रोन आधारित नवीनतम तकनीक का प्रयोग, पीपीपी मोड पर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, औषधीय पादपों के विक्रेताओं (कृषकों, स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं) के स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल किये गए हैं।
  - राज्य में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्थापना, औषधीय पादपों के लिये 'एश्योर्ड बाय-बैक' योजना, राज्य में अग्रणी निर्माताओं एवं प्रतिष्ठित विपणन एजेंसी के सहयोग से उत्तराखंड में उगाए जाने वाले प्रमुख औषधीय पादपों की ब्रांडिंग के लिये एक ऑनलाइन मंच स्थापित किया जाएगा।
  - सभी आयुष विनिर्माण इकाइयों के लिये 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त पूंजीगत सहायता, आयुष उत्पादों की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिये राज्य के 2-3 महत्त्वपूर्ण स्थानों पर सामान्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहन, आयुष उत्पादों हेतु आयुष प्रीमियम मार्क/आयुष स्टैंडर्ड मार्क प्राप्त किया जाना अनिवार्य किया गया है।
- राज्य पर्यटन नीति, 2023 के माध्यम से वेलनेस रिसोर्ट, आयुर्वेद / योग/ नेचुरोपैथी रिसोर्ट को 50 प्रतिशत तक की पूंजीगत सहायता तथा श्रेणी बी और श्रेणी सी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वेलनेस केंद्र, आयुर्वेद / योग/ नेचुरोपैथी रिसोर्ट को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
- आयुष शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आयुष कॉलेजों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) से निर्धारित मानकों को पूर्ण करने वाले आयुष कॉलेजों को 15 लाख तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है।

नोट :

उत्तराखंड में बाघों की आबादी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2006 और वर्ष 2022 के बीच उत्तराखंड में बाघों की आबादी 314% की दर से बढ़ी है। उत्तराखंड वन्यजीव अधिकारियों के अनुसार, उत्तराखंड में बाघों की आबादी का घनत्व विश्व में सबसे अधिक है।

मुख्य बिंदु:

- बाघों की आबादी जो वर्ष 2006 में 178 थी, वर्ष 2022 में बढ़कर 560 हो गई, जिसमें 314% की वृद्धि दर्ज की गई।
- राज्य में वन्य जीवों की आबादी में वृद्धि हाल के वर्षों में वन विभाग द्वारा उनके आवास की स्थिति में सुधार के लिये उठाए गए कदमों के कारण है।

नोट :

- वर्ष 2023 में बाघों के हमलों में मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या में भी मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
    - बाघों के अलावा तेंदुए, हाथी और साँप जैसे जानवरों के साथ मुठभेड़ में मारे गए लोगों की कुल संख्या वर्ष 2021 में 71, वर्ष 2022 में 82 तथा वर्ष 2023 में 66 थी।
    - मानव-पशु संघर्ष में घायल व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2021 में 361, वर्ष 2022 में 325 और वर्ष 2023 में 317 थी।
- उत्तराखंड में दो टाइगर रिज़र्व हैं:
- राजाजी राष्ट्रीय उद्यान
- कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व

राम मंदिर थीम पर उत्तरायणी पर्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले उत्तरायणी पर्व और मेले को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की थीम के साथ मनाने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

- मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने घरों में दीपोत्सव, कलश यात्रा और राम कथा का आयोजन करने का आग्रह किया है।
- उन्होंने प्रमुख नदियों के घाटों की सफाई के लिये अभियान चलाने पर भी ज़ोर दिया है।
- स्कूलों में भगवान राम के आदर्शों पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ आयोजित की जानी चाहिये।

राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह

- 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के 'प्राण-प्रतिष्ठा' समारोह की तैयारियों में शामिल हैं:
    - राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथी, शेर, भगवान हनुमान और भगवान विष्णु के 'वाहन' गरुड़ की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं।
    - प्रतिष्ठा समारोह के लिये निमंत्रण कार्ड VVIPs, पुजारियों, दानदाताओं और कई राजनेताओं सहित मेहमानों को भेज दिये गए हैं।
- श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार, मंदिर निर्माण की देखरेख करने वाली समिति:
    - पारंपरिक नागर शैली में निर्मित राम मंदिर एक तीन मंज़िला मंदिर है, जिसकी लंबाई 380 फीट (पूर्व-पश्चिम दिशा), चौड़ाई 250 फीट और ऊँचाई 161 फीट है।
    - इसमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाज़े तथा पाँच मंडप (हॉल) नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना तथा कीर्तन मंडप हैं।

सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के प्रयास

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिये प्रभावी प्रयास किये जाने चाहिये। दुर्घटना संभावित स्थानों पर सड़क सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिये।

मुख्य बिंदु:

- चारधाम यात्रा से पूर्व प्रदेश के सभी चिह्नित मार्गों पर क्रैश बैरियर का शेष कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिये।
- ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना संभावित स्थान) पर सड़क सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाना चाहिये।
- प्रदेश के पर्यटन स्थलों के निकट जिन क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ वाहन चालकों के लिये शयनगृह की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।
- बिना लाइसेंस वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

नोट :

- लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिये लघु फिल्में बनाकर व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिये।
- सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल की जानी चाहिये।
- सड़कों के किनारे अतिक्रमण रोकने के लिये पुलिस, नगर निगम, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) एवं ज़िला प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये।

उत्तराखंड में बनेंगे 5 हवाई अड्डे

चर्चा में क्यों?

सीमा सड़क संगठन (BRO) उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे विकसित करने के लिये तैयार है, जिसमें गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवीढांग शामिल हैं।

मुख्य बिंदु:

- चीन से लगी सीमा के पास संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ाने के लिये यह पहल ज़रूरी है।
- बैठक में चमोली ज़िले में रणनीतिक औली-जोशीमठ मार्ग के 10.9 किमी लंबे मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य पर भी चर्चा हुई।
- जोशीमठ के बड़गाँव से औली तक 15 किमी. वैकल्पिक मार्ग का निर्माण भी BRO को सौंपा जाना प्रस्तावित है।
- लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन ने चल रही BRO परियोजनाओं का विवरण साझा किया, जिसमें पिथौरागढ ज़िले में बलुवाकोट से तवाघाट और लिपुलेख से जोलिंगकोंग तक की सड़कें शामिल हैं।

सीमा सड़क संगठन (BRO)

- BRO की परिकल्पना और स्थापना वर्ष 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश के उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेज़ी से विकास के समन्वय के लिये की गई थी।
- यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- इसने निर्माण एवं विकास कार्यों के स्तर में व्यापक विविधता ला दी है, जिसमें हवाई क्षेत्र, निर्माण परियोजनाएँ, रक्षा कार्य और सुरंग बनाना शामिल है तथा जनता के प्रति काफी लोकप्रिय है।

PMI ने उत्तर प्रदेश को 50 ई-बसें सौंपीं

चर्चा में क्यों?

प्रमुख इलेक्ट्रिक बस निर्माता कंपनी PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी ने उत्तर प्रदेश में 50 ई-बसों की डिलीवरी की है, जो अयोध्या में उपयोग की जाएँगी।

मुख्य बिंदु:

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शून्य-कार्बन सार्वजनिक गतिशीलता पहल के तहत अयोध्या धाम बस स्टैंड से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
- इससे गणमान्य व्यक्तियों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिये अयोध्या में हरित परिवहन मिशन के पूरक सार्वजनिक परिवहन की टिकाऊ तथा आरामदायक सुविधा मिलेगी।

नेट-शून्य लक्ष्य

- नवंबर, 2021 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (COP 26) के 26वें सत्र में भारत ने वर्ष 2070 तक नेट शून्य हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की।
- भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति समानता और जलवायु न्याय के सिद्धांतों एवं सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों व संबंधित क्षमताओं के सिद्धांत पर आधारित है।

नोट :

- सरकार ने देश में तेज़ी से बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिये कई कदम उठाए हैं:
  - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने जनवरी, 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को शामिल करके 131 गैर-प्राप्ति वाले शहरों तथा 24 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के मिलियन प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
    - NCAP के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक पोर्टल PRANA लॉन्च किया गया है।

NCR और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने औद्योगिक एवं अन्य अनुप्रयोगों हेतु NCR के लिये अनुमोदित ईंधन की एक मानक सूची के साथ-साथ NCR में वायु प्रदूषण को रोकने के लिये एक नीति बनाई है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग को मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिये कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश जारी किये थे।

- यह निर्देश उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में तेंदुओं द्वारा बच्चों पर हमला करने की बढ़ती घटनाओं के बाद आया है।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों को मानव-वन्यजीव संघर्ष में मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार करने के लिये कहा गया है।
- मुख्यमंत्री ने इस संबंध में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

वन्यजीव पुनर्वास और बचाव केंद्र

- ये उन असहाय वन्यजीवों की देखभाल करने के लिये महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ हैं जो एक दुर्घटना में घायल हुए हैं या जिन्हें अवैध रूप से शिकार या कैद करने का प्रयास किया गया है और जिन्हें तत्काल चिकित्सा देखभाल एवं पुनर्वास की आवश्यकता है।

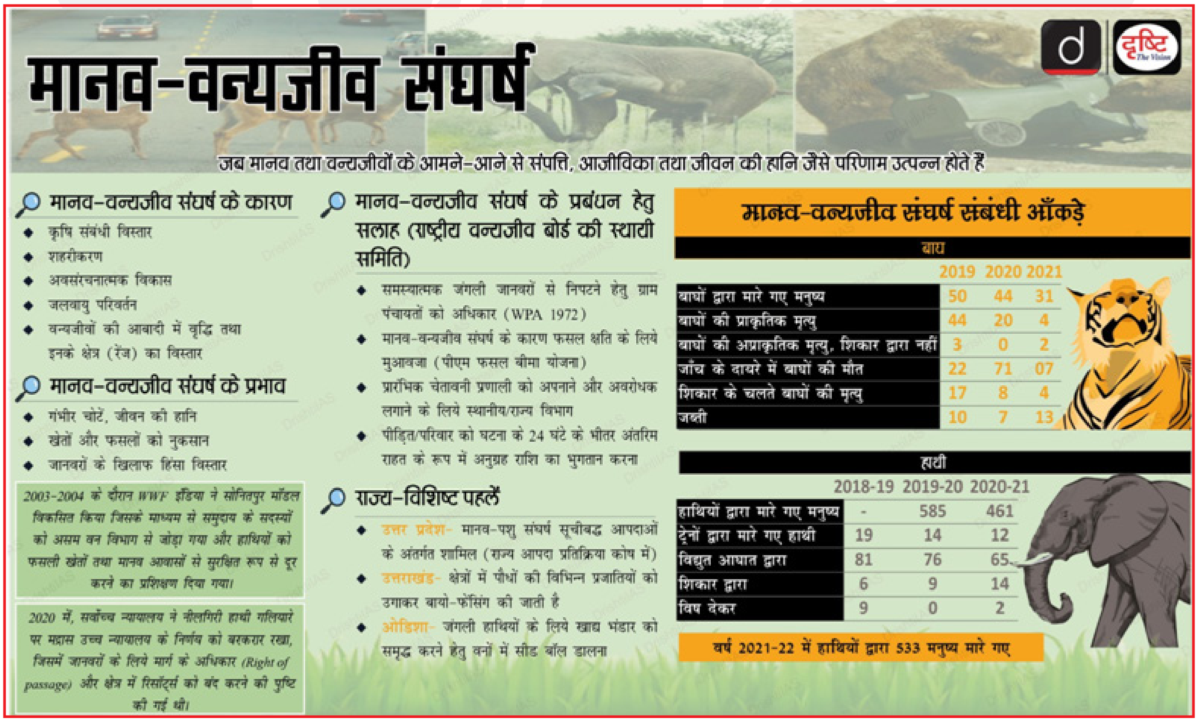

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने थर्मल पावर प्लांटों के लिये कोयला ब्लॉक का अनुरोध किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में CM धामी ने दिल्ली में केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी से मुलाकात की तथा उनसे न्यूनतम 1,000 मेगावाट के पिट-हेड थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने हेतु उत्तराखंड को प्राथमिकता के आधार पर लगभग 125 मिलियन टन की भंडारण क्षमता वाला कोयला ब्लॉक आवंटित करने का अनुरोध किया।

मुख्य बिंदु:

- उत्तराखंड उन कुछ राज्यों में से है जहाँ कोई भी थर्मल पावर स्टेशन चालू नहीं है।
- अनुकूल औद्योगिक नीति के कारण राज्य में तेज़ी से औद्योगिक विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप विद्युत की मांग में लगातार वृद्धि हुई है।
- CM के अनुसार, शीत ऋतु के दौरान विद्युत की कमी गंभीर हो जाती है क्योंकि ठंडे तापमान से नदियों में जल का प्रवाह कम हो जाता है। प्रत्येक वर्ष राज्य में विद्युत की मांग लगभग 4% से 5% की दर से बढ़ रही है।

  भारत में थर्मल पावर सेक्टर
- थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन ऐसे पावर स्टेशन हैं जो ऊष्मा से विद्युत उत्पन्न करते हैं। थर्मल पावर प्लांट ऊष्मा उत्पन्न करने के लिये ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिनमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और भूतापीय स्रोत शामिल हैं।
- थर्मल पावर सेक्टर भारत में विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जो देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 75% है।
- भारत के ताप विद्युत संयंत्र कोयले पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो अधिकतर दूसरे देशों से आयात किया जाता है। इससे आपूर्ति में व्यवधान और मूल्य में अस्थिरता हो सकती है।
- थर्मल पावर की उच्चतम स्थापित क्षमता वाले शीर्ष पाँच राज्य हैं– महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।

केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के ऊँचाई वाले इलाकों में मौसम में अचानक परिवर्तन के बाद केदारनाथ धाम में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है।

मुख्य बिंदु:

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) के अनुसार, 23 जनवरी तक केदारनाथ में न्यूनतम तापमान -16 से -18 के बीच रहने की उम्मीद है।
- बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, नीती घाटी और माणा घाटी जैसे प्रमुख स्थानों पर महत्त्वपूर्ण बर्फबारी हुई।
- विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह में बद्रीनाथ धाम के संतों को आमंत्रित किया है।
- अयोध्या में राम लला के 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के लिये सात दिवसीय वैदिक अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हुआ।
- इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिवसीय विशेष 'अनुष्ठान' की घोषणा की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के गर्भगृह के अंदर श्री राम लला की औपचारिक स्थापना की अध्यक्षता करेंगे।
- राम मंदिर 23 जनवरी, 2024 से आम जनता के लिये 'दर्शन' हेतु खुला रहेगा।

रक्षा मंत्री ने सीमा परियोजनाओं का अनावरण किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये उत्तराखंड में 35 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु:

- परियोजनाओं का निर्माण सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा 670 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, इन परियोजनाओं में सड़कें, पुल और सुरंगें शामिल हैं जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी, रक्षा तैयारी एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाना है।
- रक्षा मंत्री ने भौगोलिक और सामाजिक रूप से अलग-थलग समुदायों को राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ने में BRO द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
- रक्षा मंत्री के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण सीमावर्ती देशों में बढ़ती प्राकृतिक आपदाएँ एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा उत्पन्न करती हैं।
    - उन्होंने उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन द्वारा दिये गए असाधारण समर्थन को स्वीकार किया और संकट के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदर्शित टीम वर्क की सराहना की।
    - उन्होंने संगठन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए मुआवज़ा पेशेवरों (CPL) के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव पर प्रकाश डाला।

सीमा सड़क संगठन

- इसका गठन 7 मई 1960 को भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के उत्तर तथा उत्तर-पूर्व राज्यों के दूरदराज़ के इलाकों में बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये किया गया था।
    - इसमें 19 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सहित) और अफगानिस्तान, भूटान, म्याँमार, ताजिकिस्तान तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में बुनियादी ढाँचे के संचालन शामिल हैं।
- परियोजनाओं के समन्वय तथा शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये, भारत सरकार ने सीमा सड़क विकास बोर्ड (BRDB) की स्थापना की, जिसमें प्रधानमंत्री को बोर्ड का अध्यक्ष और रक्षा मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया।
- BRO को बर्फ हटाने जैसे कार्यों सहित इस बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने का भी कार्य सौंपा गया है। BRO नई भारत-चीन सीमा सड़कों के महत्त्वपूर्ण उन्नयन और निर्माण में सहायक है।
- लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक (DG) हैं।
- BRO का आदर्श वाक्य है श्रमेण सर्वम साध्यम है (कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है)।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण की शुरुआत की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण में 241 छात्रों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 33 लाख 52 हज़ार रुपए की राशि प्रदान की।

मुख्य बिंदु:

- यह राशि राज्य के विश्वविद्यालय परिसरों और सरकारी कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्रों को प्रदान की गई थी।
- महाविद्यालय स्तर पर तैयार की गई संकायवार मेरिट सूची में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर 3000, 2000 और 1500 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- अन्य कक्षाओं के लिये वितरित छात्रवृत्ति संबंधित संस्थान स्तर से समर्थ पोर्टल पर सत्यापन के बाद की जाएगी।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सामान्य परिवारों के छात्रों की प्रतिभा को आगे लाना है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना

- इसकी घोषणा 31 मई 2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी।
- योजना शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य छात्रों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- केवल स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र ही छात्रवृत्ति के लिये पात्र हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

- यह सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2013 को शुरू की गई एक पहल है।
- इसे सिस्टम के भीतर धोखाधड़ी प्रथाओं को कम करने के साथ-साथ लाभार्थियों को सूचना और धन के हस्तांतरण को सुव्यवस्थित तथा तीव्र करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- DBT अधिक कुशल और पारदर्शी वितरण तंत्र सुनिश्चित करते हुए, इच्छित प्राप्तकर्त्ताओं को सरकारी सब्सिडी, लाभ तथा सहायता के सीधे हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।

उत्तराखंड ने पवलगढ़ कंज़र्वेशन रिज़र्व का नाम बदला

चर्चा में क्यों ?

अयोध्या मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठा से पहले, रामनगर वन प्रभाग में 5,800 हेक्टेयर के पवलगढ़ कंज़र्वेशन रिज़र्व का नाम बदलकर सीताबनी कंज़र्वेशन रिज़र्व कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु:

अधिकारियों के अनुसार, रिज़र्व के अंदर माता सीता को समर्पित एक प्राचीन मंदिर तथा महर्षि वाल्मिकी आश्रम है, कहा जाता है कि अयोध्या छोड़ने के बाद वह अपने बेटों लव और कुश के साथ यहीं रुकी थीं।

- दोनों संरचनाओं का रखरखाव भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है।

पवलगढ़ कंज़र्वेशन रिज़र्व (PCR)

- यह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित है। इसे दिसंबर, 2012 में एक कंज़र्वेशन रिज़र्व के रूप में नामित किया गया था।
- PCR का कुल क्षेत्रफल 58.25 वर्ग किमी. है जो रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के सुंदर, विशाल और समृद्ध जंगलों में स्थित है।
- यह रिज़र्व स्तनधारियों की 33 से अधिक प्रजातियों, पक्षियों की 365 प्रजातियों और वनस्पतियों की 400 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है।

नोट:

- वर्ष 2021 में, केंद्रीय वन राज्य मंत्री ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की अपनी यात्रा के दौरान आगंतुक पुस्तिका में लिखा कि इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर देना चाहिये, क्योंकि वन अधिकारियों के अनुसार कॉर्बेट का पहले रामगंगा नाम था।
  - यह रिज़र्व वर्ष 1936 में अस्तित्व में आया और संयुक्त प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर के नाम पर इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया।
  - इसे दिसंबर 2012 में रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया।

उत्तराखंड के हवाई अड्डे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय होंगे

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देहरादून और पंतनगर में हवाई अड्डे जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करेंगे।

मुख्य बिंदु:

- देहरादून में जॉली ग्रांट और उधम सिंह नगर में पंतनगर राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं।
  - जॉली ग्रांट मसूरी के सुरम्य शहर का प्राथमिक हवाई अड्डा और निकटतम प्रवेश द्वार है।
  - पंतनगर नैनीताल के लिये निकटतम हवाई अड्डा है।
- इस कदम से कनेक्टिविटी बढ़ने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने, राज्य में आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
- इसके अलावा, सीएम ने देहरादून के पास एक नई टाउनशिप के विकास के लिये एक महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोण का भी खुलासा किया।

नोट :

- यह टाउनशिप देहरादून ज़िले के कालसी के पास हरिपुर में स्थापित की जाएगी, जो निवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगी।
- यह विकास राज्य की बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिये सतत् शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण के सरकार के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जारी किया कैलेंडर

चर्चा में क्यों?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तराखंड के वार्षिक कैलेंडर "सशक्त नेतृत्व, समृद्ध उत्तराखंड" का विमोचन किया।

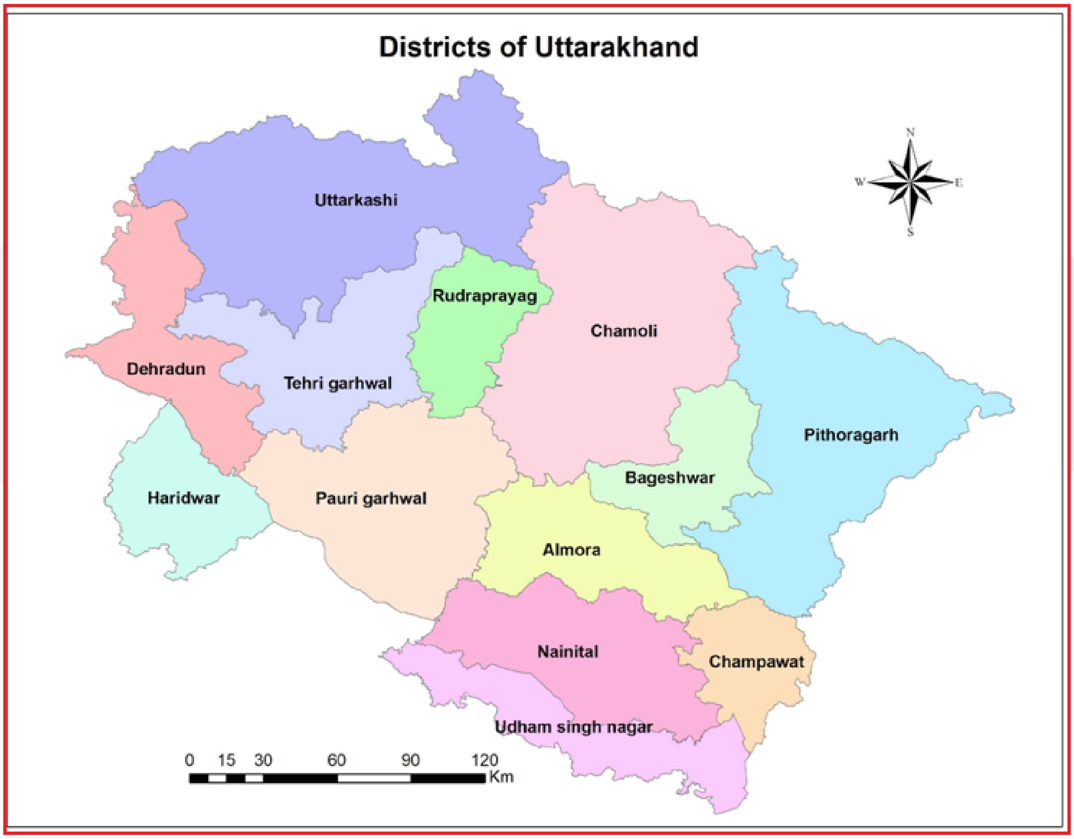

मुख्य बिंदु:

- इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के सभी 13 ज़िलों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों, स्थानीय उत्पादों, प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक स्थलों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया।
- राज्य की पर्यटन नीति, सौर ऊर्जा नीति, सशक्त महिला-समृद्ध राज्य, युवाओं के प्रति संवेदनशीलता और निवेश-रोज़गार-समृद्धि के लिये सरकार द्वारा किये गये कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया।
- सीएम ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश:
  - जल संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास किये जाने चाहिये तथा इसके लिये जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिये।
  - लोगों को डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक करना और नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाना।

- प्रदेश में वोकल फॉर लोकल को तेज़ी से बढ़ावा दिया जाए।
- राज्य में पर्यटन को और अधिक तेज़ी से बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने पर निरंतर कार्य करना।
- खान-पान, खेल को अपनी दिनचर्या में शामिल करने तथा नशे और लत से दूर रहने के लिये समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना।

'विकसित उत्तराखंड' : गणतंत्र दिवस परेड की झाँकी

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2024 में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली गणतंत्र दिवस परेड की झाँकी 'विकसित उत्तराखंड' की थीम को प्रदर्शित करेगी।

- यह निर्णय राज्य की झाँकी 'मानसखंड' की सफलता के बाद लिया गया है, जिसने वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था।

मुख्य बिंदु:

- अधिकारियों के मुताबिक, सामने वाले हिस्से में पारंपरिक पोशाक पहने एक कुमाऊंनी महिला गर्मजोशी से स्वागत कर रही है।
- झाँकी में राज्य पक्षी मोनाल के साथ-साथ मडुवा, झंगोरा, रामदाना और कौनी जैसी पारंपरिक फसलों की कृषि को भी दिखाया गया है। झाँकी के मध्य भाग में होमस्टे एक प्रमुख हिस्सा है।
- झाँकी के समापन खंड में राज्य की विकासात्मक परियोजनाओं के महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को दर्शाया गया है, जैसे कि चारधाम मार्ग की ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, रोपवे सिस्टम और माणा के लिये बढ़ी हुई सड़क कनेक्टिविटी।

झंगोरा

- यह नैतिक रूप से उत्तरकाशी घाटी, उत्तराखंड के किसानों से प्राप्त किया गया है। यह मानव जाति के लिये ज्ञात सबसे पुराने अनाजों में से एक है, जो लगभग 3000 वर्ष पुराना है।
- इसे सामान्यत: बंगाली में श्यामा, गुजराती में मोराइयो, हिंदी में संवा चावल, कन्नड़ में उदलु, तमिल में तेलगु और कुथिराईवली के नाम से जाना जाता है।

रामदाना

- इसे हाथ से चुना जाता है और हिमालय घाटी से प्राप्त किया गया है। यह कश्मीर से भूटान तक फैले हिमालय क्षेत्र में 1,000-3,000 मीटर की ऊँचाई के बीच बहुतायत में उगता है।
- यह एक संपूर्ण प्रोटीन है, जिसमें सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड और 14% प्रोटीन होता है। इसे अमरंथ, चुआ, चौलाई और पुंगिकिरी के नाम से भी जाना जाता है।

मोनाल

- हिमालयन मोनाल, जिसे इम्पेयन मोनाल, इम्पेयन फैजेन्ट/तीतर के नाम से भी जाना जाता है, तीतर परिवार, फासियानिडे का एक पक्षी है।
- यह उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसे वर्ष 2018 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में चुना गया है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार हिमालयन मोनाल अनुसूची- I सूचीबद्ध एक पक्षी है और IUCN द्वारा इसे 'कम चिंताजनक (LC)' प्रजातियों की श्रेणी में रखा गया है।

नोट :

गन्ने की किस्म का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने चालू पेराई सत्र 2023-24 के लिये गन्ने की अगेती और सामान्य किस्म का राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) क्रमशः 375 रुपए तथा 365 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की थी।

मुख्य बिंदु:

- गन्ने का मूल्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर तय करती हैं।
- केंद्र सरकार: उचित और लाभकारी मूल्य (FRP):
  - केंद्र सरकार FRP की घोषणा करती है जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्धारित होती है, जिसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा घोषित किया जाता है।
    - CCEA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
  - FRP, गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- राज्य सरकार: राज्य परामर्शित मूल्य (SAP):
  - SAP की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की सरकारों द्वारा की जाती है।
  - SAP आमतौर पर FRP से अधिक होता है।

गन्ने की वृद्धि के लिये भौगोलिक स्थितियाँ

- तापमान: गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21-27 °C के मध्य।
- वर्षा: लगभग 75-100 सेमी.।
- मृदा का प्रकार: गहरी समृद्ध दोमट मृदा।
- शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य: महाराष्ट्र> उत्तर प्रदेश> कर्नाटक।

उत्तराखंड का जादुंग गाँव, पुनर्वास के लिये तैयार

चर्चा में क्यों?

"अपनी तरह की पहली (First-of-Its-Kind)" पहल में, उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी ज़िले के जादुंग गाँव का एक प्रमुख "पर्यटन स्थल" के रूप में पुनर्निर्माण और पुनर्वास करने का निर्णय लिया है, जिसे वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद से निवासियों द्वारा खली कर दिया गया था।

- यह गाँव वर्ष 1962 से भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के नियंत्रण में है।

मुख्य बिंदु:

- पहल के हिस्से के रूप में, पर्यटन विभाग का लक्ष्य गाँव का पुनर्निर्माण करने के लिये मूल घर मालिकों के वंशजों को वापस बुलाना है, जो अब आस-पास के गाँवों में रहते हैं।
- अक्तूबर-नवंबर 1962 के युद्ध ने इस क्षेत्र को वीरान कर दिया था, जिससे भारत और चीन के बीच संबंधों पर असर पड़ा, कुछ सीमा विवाद अभी भी अनसुलझे थे।
  - यह एक ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है (लद्दाख की तरह) यहाँ उचित सड़क संपर्क है, जो इसे एक संभावित पर्यटन स्थल बनाता है।
- पहले चरण में, पर्यटन विभाग छह "जीर्ण" घरों का नवीनीकरण करेगा और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करेगा तथा ग्रामीणों द्वारा संचालित स्थानीय वास्तुकला में होमस्टे के रूप में बढ़ावा देगा।
- यह पहल जादुंग गाँव के लिये "स्वरोज़गार के अवसर" उत्पन्न करेगी, साथ ही सभी को एक अद्वितीय पर्यटन स्थल भी प्रदान करेगी।

- ग्रामीणों को कम से कम 10 वर्षों तक होमस्टे का संचालन करना होगा, जिसके संचालकों का चयन उत्तरकाशी ज़िला प्रशासन द्वारा गाँव के मूल निवासियों के आवेदन के माध्यम से किया जाएगा।
- पर्यटन विभाग होमस्टे संचालकों को कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की भी योजना बना रहा है, जिसे विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित किया जाएगा। विभाग इन होमस्टे के विपणन और प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा।
- अधिकारियों के मुताबिक, यह योजना सरकारी हस्तक्षेप से रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में मील का पत्थर बनेगी और पर्यटन के नए अवसर भी उत्पन्न करेगी।

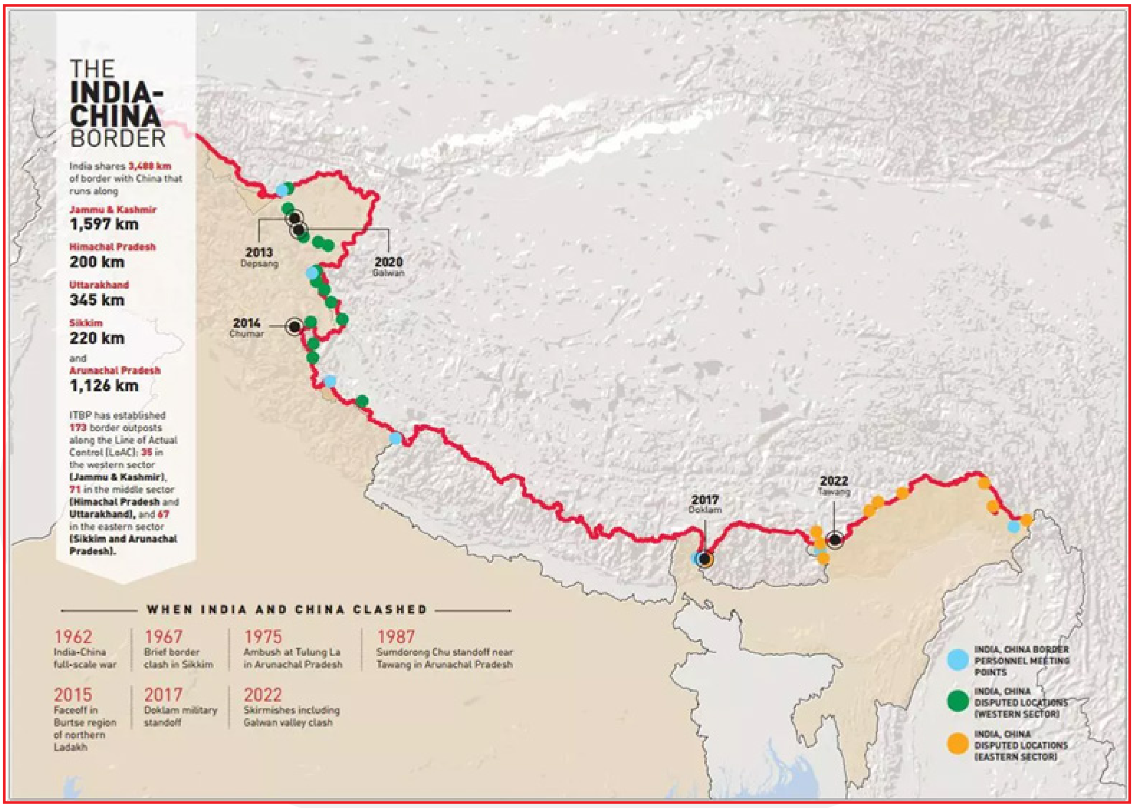

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- यह एक समर्पित बल है जो तिब्बत (चीन) के साथ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिये ज़िम्मेदार है।
- ITBP की स्थापना 24 अक्तूबर, 1962 को भारत-चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा रक्षक पुलिस बल है जिसके पास ऊँचाई वाले अभियानों की विशेषज्ञता है।
- ITBP को प्रारंभ में 'केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल' (CRPF) अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित किया गया था। हालाँकि वर्ष 1992 में संसद ने ITBP अधिनियम लागू किया और वर्ष 1994 में इसके संबंध में नियम बनाए गए।
- ITBP को नक्सल विरोधी अभियानों सहित विभिन्न आंतरिक सुरक्षा कर्त्तव्यों के लिये भी तैनात किया गया है। यह बल उच्च ऊँचाई वाले बचाव और पर्वतारोहण अभियानों में अपनी विशेषज्ञता के लिये जाना जाता है।

नोट:

- भारत और चीन के बीच सीमा पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है तथा कुछ हिस्सों पर कोई पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) नहीं है।
- वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद LAC अस्तित्व में आई।

- भारत-चीन सीमा को तीन सेक्टरों में बाँटा गया है:
  - पश्चिमी क्षेत्र: लद्दाख
  - मध्य क्षेत्र: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
  - पूर्वी क्षेत्र: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग में किया 'रोड शो'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में प्राचीन देवल से अगस्त्यमुनि के खेल मैदान तक 'रोड शो' किया और करीब 468 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम में 467 करोड़ रुपए से अधिक की कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन किया गया।
- इस मौके पर सीएम ने महिलाओं से सरकार की महाप्रसाद योजना से जुड़ने के बाद उनकी आजीविका में आये बदलाव के बारे में भी जानकारी ली।
  - केदारनाथ यात्रा से जुड़े विभिन्न महिला समूहों ने वर्ष 2023 की यात्रा के दौरान ₹70 लाख से अधिक का व्यवसाय किया था।
  - इसके अलावा महिलाओं ने स्थानीय हर्बल धूप, चूरमा, बेलपत्री, शहद, जूट, रेशम की थैलियाँ आदि के व्यवसाय से 5 लाख रुपए की कमाई की है।
  - विभिन्न महिला समूहों की 500 से अधिक महिलाओं को इससे रोज़गार भी मिला।

'प्रसाद' (PRASHAD) योजना:

- पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive'- PRASAD)' शुरू किया गया था।
- अक्तूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्द्धन अभियान' (National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Heritage Augmentation Drive- PRASHAD) राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया।
- प्रसाद योजना के तहत विकास के लिये कई धार्मिक शहरों/स्थलों की पहचान की गई है जैसे- अमरावती और श्रीशैलम (आंध्र प्रदेश), कामाख्या (असम), परशुराम कुंड (लोहित ज़िला, अरुणाचल प्रदेश), पटना और गया (बिहार) आदि।

पवित्र भूमि को जोड़ने वाली हवाई सेवा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तीन वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद पिथौरागढ़ के नैनी-सैनी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू हुआ।

मुख्य बिंदु:

- उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने के बाद, जिसे वर्ष 2020 की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था, विमानन कंपनी फ्लाईबिग सप्ताह में तीन बार सोमवार, मंगलवार व शुक्रवार को देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच 19 सीटों वाला विमान संचालित करेगी।
- हवाई अड्डे से सेवाओं की बहाली, जिसे जल्द ही पंतनगर और फिर गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे तक बढ़ाया जाएगा, रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण सीमावर्ती ज़िले के लिये महत्त्वपूर्ण होगी।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के अनुसार, देहरादून तथा पिथौरागढ़ के बीच हवाई कनेक्टिविटी से मानसखंड क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।

- आदि कैलाश शिखर और जागेश्वर धाम के दर्शन के लिये प्रधानमंत्री की जोलिंगकोंग यात्रा से पर्यटकों में रुचि जागृत हुई, जिन्होंने बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम ज्ञात धार्मिक स्थलों की यात्रा करना शुरू कर दिया है।

आदि कैलाश शिखर

- आदि कैलाश, जिसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश, बाबा कैलाश या जोंगलिंगकोंग पीक के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक पर्वत है।

जागेश्वर धाम

- यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में स्थित एक हिंदू तीर्थस्थल है। यह स्थल भारतीय कानूनों के तहत संरक्षित है और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

✦ ✦ ✦ ✦